ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु योजनाओं की गलत ढंग से मॉनीटरिंग

294. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिं यादव:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाओं की सही ढंग से मानीटरिंग नहीं होती है जिसके कारण इन योजनाओं से लोगों को विशेष फायदा नहीं हो रहा है; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने अपनी योजनाओं की निगरानी के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित की है जिससे इन योजनाओं के लाभ निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से लक्षित गरीबों तक पहुंचाना सुनिश्चित हो सके:—

1. मासिक प्रगति रिपोर्ट/रिटर्न।
2. राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा गहन क्षेत्र निरीक्षण।
3. मंत्रालय की क्षेत्र अधिकारी योजना।
4. विभिन्न समितियों जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा समीक्षा।
5. राज्यों के ग्रामीण विकास सचिवों तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों का सम्मेलन।
6. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में रुकावटों का पता लगाने और प्रभाव का आकलन करने के लिए समवर्ती मूल्यांकन।
7. वीडियो कांफ्रेंस।

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, राज्य/जिला/ब्लाक स्तरों पर निगरानी एवं सतर्कता समितियां बनाने के निर्देश दिए गए हैं जिनमें संसद और विधायकों को भी शामिल किया गया है।

स्वरोजगार कार्यक्रम में ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण, योजना के अन्तर्गत युवकों को रोजगार

295. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "स्व-रोजगार कार्यक्रम में ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण" योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवा अभी भी बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में रोजगार न पाने वाले ऐसे युवाओं की संख्या क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आकलन न करने का क्या कारण है, और

(ङ) क्या सरकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सफलता या असफलता का मूल्यांकन करने का विचार रखती है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) ट्राइसेम कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण गरीबों को बुनियादी तकनीकी तथा उद्यम संबंधी कौशल उपलब्ध कराना है ताकि वे स्वमजदूरी रोजगार शुरू कर सकें। कार्यक्रम की कारगरता का पता लगाने के लिए ख्यातिप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से ट्राइसेम का एक तीव्र मूल्यांकन (जून-अगस्त, 93) कराया गया था, जिससे यह पता चला कि 47.19% प्रशिक्षित युवा बेरोजगार थे।

(ख) सरकार ने ट्राइसेम योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ पहल की है। राज्यों से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ ट्राइसेम के बेहतर तालमेल को बढ़ावा देने, सेवा क्षेत्र और नियमित क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण; अपंग लोगों तथा महिलाओं का प्रशिक्षण; निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षण; आदि पर अधिक बल देने का अनुरोध किया गया है। वजीफे की दरें बढ़ा दी गयी हैं।

(ग) 8वीं योजनावधि तथा वर्ष 1997-98 के दौरान प्रशिक्षित युवाओं तथा प्रशिक्षित युवाओं, जो स्व/मजदूरी रोजगार में लगे हुए थे, की कुल संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(घ) और (ङ) 1993-94 के दौरान तीव्र मूल्यांकन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया था।